OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 3 [May- Jun] Year 2025*

IJCRM

International Journal of Contemporary Research In Multidisciplinary

Research Article

दक्षिण एशिया में बदलती सामरिक और भू-राजनीतिक परिस्थिति: भारत के समक्ष उभरता हुआ तुर्की-पाकिस्तान-चीन गठजोड़

Dr. Arvind Kumar*

Assistant professor, Department of Defence and Strategic Studies, A.N.D.K.PG College, Babhnan Gonda, Uttar Pradesh, India

Corresponding Author: ***Dr. Arvind Kumar**

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15543155

सारांश

दक्षिण एशिया वर्तमान में सामरिक और भू-राजनीतिक परिवर्तनों के एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। इस अध्ययन में तुर्की, पाकिस्तान और चीन के त्रिपक्षीय गठजोड़ (TPC) के उदय और भारत की सुरक्षा, विदेश नीति तथा क्षेत्रीय नेतृत्व पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। यह गठबंधन केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैचारिक, धार्मिक और वैश्विक शक्ति संतुलन की आकांक्षाएं भी निहित हैं। चीन की आर्थिक आक्रामकता, पाकिस्तान की भारत-विरोधी रणनीति और तुर्की की इस्लामी नेतृत्व की महत्वाकांक्षा मिलकर एक ऐसे गठजोड़ का निर्माण करती हैं जो दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति को चुनौती देता है। इस शोध में क्षेत्रीय देशों (जैसे नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव) पर इस गठजोड़ के प्रभाव, भारत की "Neighborhood First" नीति की चुनौतियाँ, समुद्री सुरक्षा पर खतरे, तथा कश्मीर और आतंकवाद को लेकर वैश्विक दबाव की रणनीति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। अंततः, भारत के लिए सामरिक आधुनिकीकरण, बहुपक्षीय कूटनीतिक सक्रियता, जल कूटनीति और सूचना युद्ध जैसी रणनीतियों की आवश्यकता पर बल दिया गया है ताकि वह इस नई भू-रणनीतिक वास्तविकता का प्रभावी ढंग से सामना कर सके।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 11-05-2025
- **Accepted:** 25-05-2025
- **Published:** 28-05-2025
- **IJCRM:**4(3); 2025: 206-212
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

Kumar A. दक्षिण एशिया में बदलती सामरिक और भू-राजनीतिक परिस्थिति: भारत के समक्ष उभरता हुआ तुर्की-पाकिस्तान-चीन गठजोड़. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(3):206-212.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मूल शब्द: दक्षिण एशिया, तुर्की-पाकिस्तान-चीन गठजोड़, भारत की सुरक्षा, भू-राजनीतिक संतुलन, कश्मीर नीति, समुद्री सुरक्षा

© 2025 Dr. Arvind Kumar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

परिचय

दक्षिण एशिया वर्तमान में एक तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जहां सामरिक संतुलन और भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से पुनर्निर्मित हो रहे हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या घनत्व, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के निकटता इसे वैश्विक शक्तियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। शीत युद्ध के बाद की द्विध्रुवीयता के अंत और वैश्वीकरण की लहरों के बीच, दक्षिण एशिया ने चीन के उदय, भारत की प्रगति, और पाकिस्तान की रणनीतिक द्वंद्व नीति के समागम को देखा है। हाल ही में जिस गठजोड़ ने इस क्षेत्र की सामरिक स्थिरता को नई चुनौती दी है, वह है तुर्की, पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ता हुआ रणनीतिक और राजनीतिक सहयोग।

इस त्रिपक्षीय गठजोड़ का उदय केवल आर्थिक या सैन्य साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचारधारात्मक, धार्मिक और वैश्विक शक्ति संतुलन के उद्देश्यों की भी झलक मिलती है। चीन, जो पहले ही 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने में सफल रहा है, अब पाकिस्तान के साथ अपने 'ऑल वेदर' संबंधों को और गहरा कर चुका है। पाकिस्तान, जो स्वयं को भारत के विरुद्ध सामरिक संतुलन स्थापित करने के लिए बार-बार बाहरी शक्तियों की ओर देखता रहा है, अब तुर्की को भी अपने रणनीतिक सहयोगी के रूप में उभारने में सफल रहा है। तुर्की, जो ऐतिहासिक रूप से एक इस्लामी नेतृत्वकारी भूमिका की पुनः प्राप्ति के प्रयास में है, पाकिस्तान के साथ रक्षा, तकनीक और धार्मिक एकजुटता के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

यह गठजोड़ न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित करता है, बल्कि भारत के लिए गंभीर सामरिक और भू-राजनीतिक चुनौती उत्पन्न करता है। भारत, जो दक्षिण एशिया में शांति, स्थायित्व और बहुपक्षीय सहयोग का पक्षधर रहा है, अब एक ऐसे त्रिकोणीय सहयोग से घिरता दिखाई दे रहा है, जो उसकी सुरक्षा, विदेश नीति और क्षेत्रीय नेतृत्व की स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, और अब तुर्की की भारत-विरोधी बयानबाज़ी तथा कश्मीर मुद्दे पर उसकी सक्रियता, मिलकर भारत के लिए एक बहुआयामी रणनीतिक संकट का संकेत देते हैं।

भू-राजनीतिक दृष्टि से यह गठजोड़ केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हिंद महासागर क्षेत्र, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में भी शक्ति संतुलन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। चीन की आर्थिक शक्ति, पाकिस्तान की रणनीतिक अवस्थिति और तुर्की की वैचारिक आक्रामकता मिलकर भारत की "एक्ट ईस्ट", "नेबरहुड फर्स्ट" तथा "इंडो-पैसिफिक" नीति के समक्ष नई चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। यह गठबंधन भारत को अपनी सामरिक क्षमताओं, कूटनीतिक रणनीतियों और वैश्विक गठबंधनों को पुनर्संतुलित करने के लिए प्रेरित करता है।

इस प्रस्तावना के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया में उभरता हुआ तुर्की-पाकिस्तान-चीन गठजोड़ केवल एक राजनीतिक समागम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित भू-रणनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करना, इस्लामी सहयोग को सशक्त करना और चीन के वैश्विक वर्चस्व को मजबूती देना है। भारत के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह इन विकसित हो रहे समीकरणों का गहन विश्लेषण करे और एक सशक्त, बहुपक्षीय तथा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाए जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस त्रिपक्षीय गठजोड़ के रणनीतिक उद्देश्य (Strategic Intent and Mutual Interests)

21वीं सदी के मध्य चरण में दक्षिण एशिया एक बार फिर भू-राजनीतिक खींचतान का केंद्र बनता जा रहा है, और इसके केंद्र में उभरता हुआ तुर्की-पाकिस्तान-चीन (TPC) त्रिकोणीय गठजोड़ है। यह गठजोड़ केवल सामरिक सहयोग का मंच नहीं है, बल्कि इसमें इस्लामी नेतृत्व की आकांक्षाएं, भारत-विरोधी रणनीतियाँ, और वैश्विक शक्ति समीकरणों में परिवर्तन लाने की प्रवृत्ति अंतर्निहित है। यह गठबंधन एक साझा उद्देश्य के साथ भारत के उदय को रोकने, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को पुनः परिभाषित करने और बहुपक्षीय संस्थानों में अपना दबदबा स्थापित करने की दिशा में कार्यरत है।

इस्लामिक देशों में नेतृत्व के लिए तुर्की की महत्वाकांक्षा

तुर्की की राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगान की विदेश नीति में "पैक्स ओटोमानिका" यानी उस्मानी विरासत को पुनर्जीवित करने की झलक मिलती है। एर्दोगान खुद को इस्लामिक जगत के वैकल्पिक नेता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर ऐसे समय में जब सऊदी अरब और ईरान के बीच नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा जारी है। तुर्की, ओआईसी (Organization of Islamic Cooperation) के माध्यम से कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाकर भारत की आलोचना करता रहा है। पाकिस्तान के साथ तुर्की के संबंध केवल धार्मिक सहानुभूति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सामरिक और वैचारिक समर्थन के आधार पर मजबूत हुए हैं।

तुर्की का भारत-विरोधी बयानबाज़ी में सक्रिय रहना, जैसे कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की नीतियों की आलोचना करना, उसके इस्लामी नेतृत्व की आकांक्षा का हिस्सा है। वह मुस्लिम बहुल देशों के साथ सहयोग बढ़ाकर एक ऐसा वैकल्पिक शक्ति केंद्र बनाना चाहता है जो पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध कर सके। पाकिस्तान इस रणनीति में तुर्की का स्वाभाविक साझेदार है, वहीं चीन इसे आर्थिक और सामरिक विस्तार के लिए अवसर के रूप में देखता है।

पाकिस्तान की भारत-विरोधी नीति में समर्थन की तलाश

पाकिस्तान की विदेश नीति में भारत विरोध एक स्थायी तत्व रहा है। चाहे कश्मीर मुद्दा हो, सीमापार आतंकवाद या अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि खराब करने के प्रयास – पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत के खिलाफ सक्रिय रहा है। लेकिन आर्थिक कंगाली, वैश्विक अलगाव और आतंरिक अस्थिरता ने पाकिस्तान को ऐसे साझेदारों की तलाश में ढकेल दिया है जो उसके रणनीतिक लक्ष्यों को साझा करते हों। तुर्की और चीन इस आवश्यकता को पूरा करते हैं।

तुर्की पाकिस्तान को कूटनीतिक समर्थन देता है, वहीं चीन उसे आर्थिक और रक्षा सहायता प्रदान करता है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की भूमिका को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा स्पष्ट संकेत दिए गए हैं। यह हमला न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि पाकिस्तान अब भी आतंकवाद को एक

© 2025 Dr. Arvind Kumar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

रणनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में तुर्की और चीन का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना भारत की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ाता है।

चीन की दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ाने की रणनीति

चीन का दीर्घकालिक उद्देश्य है — एशिया में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देना और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करना। भारत, चीन की इस रणनीति में सबसे बड़ा बाधक है, विशेषकर इंडो-पैसिफिक रणनीति, क्वाड (QUAD) गठबंधन और दक्षिण एशियाई देशों में भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए। चीन ने पाकिस्तान के साथ "ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप" को सशक्त बनाया है और अब तुर्की के साथ भी अपने संबंधों को बहुआयामी बना रहा है।

साउथ एशिया में चीन की गहरी घुसपैठ – चाहे वह नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या मालदीव हो – भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को चुनौती देती है। तुर्की के माध्यम से चीन अब इस्लामिक विश्व के साथ संवाद बढ़ा रहा है और पाकिस्तान के माध्यम से भारत की पश्चिमी सीमाओं पर सामरिक दबाव बना रहा है। चीन का कश्मीर मुद्दे पर दोहरा रवैया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) के तहत किए गए निवेश भारत की संप्रभुता के लिए सीधा खतरा हैं।

तकनीकी, रक्षा और आर्थिक सहयोग

यह त्रिपक्षीय गठजोड़ केवल वैचारिक या रणनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि ठोस तकनीकी, रक्षा और आर्थिक सहयोग के माध्यम से भी सशक्त हो रहा है। तुर्की और पाकिस्तान ने संयुक्त रूप से ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए कई पहल की हैं — उदाहरण के लिए बायकर ड्रोन टेक्नोलॉजीज़। चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल और परमाणु तकनीक में निरंतर सहयोग प्रदान किया है, जिससे दक्षिण एशिया में असंतुलन बढ़ा है।

आर्थिक मोर्चे पर भी यह गठजोड़ चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के तहत एक साझा ढांचा तैयार कर रहा है। पाकिस्तान पहले ही चीन का कर्जदार बन चुका है, वहीं तुर्की भी अब चीनी निवेश और व्यापार का लाभ लेने की दिशा में बढ़ रहा है। इस आर्थिक निर्भरता का राजनीतिक और सामरिक प्रभाव साफ दिखाई देता है, जब ये तीनों देश वैश्विक मंचों पर एक-दूसरे का समर्थन करते हैं — विशेषकर भारत के खिलाफ मुद्दों पर।

3. दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन पर प्रभाव

तुर्की, पाकिस्तान और चीन के उभरते त्रिकोणीय गठजोड़ ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। यह न केवल भारत की पारंपरिक रणनीतिक स्थिति के लिए एक चुनौती बन चुका है, बल्कि इसके व्यापक प्रभाव भारत के पड़ोसी देशों की विदेश नीति, रक्षा संधियों और भू-राजनीतिक झुकावों पर भी स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। इस गठजोड़ की विशेषता यह है कि तीनों देश भारत के रणनीतिक हितों को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक समन्वित नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

भारत के पड़ोसी देशों पर इस गठजोड़ का प्रभाव

भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र रहे नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव आज चीन और पाकिस्तान के रणनीतिक निवेश और कूटनीतिक हस्तक्षेप के चलते भारत से संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्की, जो अब तक इस क्षेत्र में सीमित भूमिका निभा रहा था, हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ सैन्य और सांस्कृतिक साझेदारी के माध्यम से क्षेत्रीय राजनीति में प्रवेश कर चुका है। वह ओआईसी (Organization of Islamic Cooperation) मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाकर भारत के खिलाफ एक वैकल्पिक इस्लामी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है।

अफगानिस्तान

तालिबान के पुनः सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव सीमित हो गया है। पाकिस्तान और चीन दोनों ने तालिबान शासन को धीरे-धीरे मान्यता देने और रणनीतिक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने की दिशा में काम किया है। तुर्की ने भी काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा और पुनर्निर्माण में रुचि दिखाकर वहां अपनी भूमिका बढ़ाने की कोशिश की है। यह त्रिकोणीय गठबंधन अफगानिस्तान में भारत के दीर्घकालिक निवेश और रणनीतिक कनेक्टिविटी परियोजनाओं (जैसे चाबहार पोर्ट और जारांज-देलाराम हाईवे) के प्रभाव को सीमित करने का प्रयास कर रहा है।

नेपाल

नेपाल, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भारत के निकट रहा है, आज चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के प्रभाव में आ चुका है। पाकिस्तान और तुर्की ने नेपाल में धार्मिक-शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से इस्लामिक नेटवर्क फैलाने की दिशा में काम किया है, जिससे भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान चिंतित हैं। 2020 में नेपाल द्वारा नए राजनीतिक मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को शामिल करना भारत-नेपाल संबंधों में तनाव का संकेत था, जो चीन के परोक्ष समर्थन से उत्पन्न हुआ।

श्रीलंका

श्रीलंका में चीन की 'Debt Trap Diplomacy' का उदाहरण हंबनटोटा पोर्ट है, जिसे 99 वर्षों की लीज़ पर चीन को देना पड़ा। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही श्रीलंका के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। तुर्की ने हाल ही में श्रीलंका को ड्रोन तकनीक देने की बात की है, जबकि पाकिस्तान श्रीलंका को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। इससे भारत की क्षेत्रीय नौसैनिक श्रेष्ठता को चुनौती मिलती है।

मालदीव

मालदीव में हाल ही में राष्ट्रपति मोहम्मद मुईज़्ज़ू के सत्ता में आने के बाद 'India Out' अभियान को बल मिला है। यह अभियान प्रत्यक्ष रूप से चीन और पाकिस्तान समर्थित सूचना तंत्र से संचालित होता प्रतीत होता है। मालदीव ने चीनी कंपनियों के साथ ढांचागत विकास परियोजनाएं शुरू की हैं। तुर्की भी मालदीव में अपने इस्लामी संगठनों और शैक्षणिक नेटवर्क के माध्यम से एक वैकल्पिक प्रभाव बढ़ा रहा है।

© 2025 Dr. Arvind Kumar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

भारत की "Neighborhood First" नीति की चुनौतियाँ :

भारत की "Neighborhood First" नीति का उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना था। लेकिन तुर्की-पाकिस्तान-चीन त्रिकोण के आक्रामक कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयासों के चलते भारत की इस नीति को कई बार झटका लगा है। पड़ोसी देशों के अंदर राजनीतिक अस्थिरता, भारत विरोधी भावनाओं का उभार, और चीन के आर्थिक व तुर्की-पाकिस्तान के सांस्कृतिक-धार्मिक प्रभाव ने भारत की पहल को सीमित कर दिया है।

भारत ने BIMSTEC, SAGAR (Security and Growth for All in the Region) और IORA (Indian Ocean Rim Association) जैसे मंचों के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में काम किया है, लेकिन इन प्रयासों को चीन-पाकिस्तान की कूटनीतिक बाधाएं लगातार चुनौती देती रही हैं। तुर्की के हालिया हस्तक्षेप इस प्रतिस्पर्धा को एक नया वैचारिक आयाम भी देते हैं।

सामरिक असंतुलन की स्थिति

इस त्रिपक्षीय गठजोड़ ने दक्षिण एशिया में एक नया सामरिक असंतुलन पैदा कर दिया है। चीन द्वारा हिंद महासागर में पनडुब्बी तैनात करना, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चीन को सौंपना, और तुर्की का रक्षा तकनीक जैसे ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली में सहयोग करना इस बात का संकेत है कि भारत के लिए बहुस्तरीय खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषकर तुर्की के 'Bayraktar TB2' जैसे ड्रोन, जिन्हें उसने अजरबैजान, लीबिया और यूक्रेन में प्रभावी रूप से इस्तेमाल किया है, अब पाकिस्तान को निर्यात किए जा रहे हैं। इससे भारत की पश्चिमी सीमाओं पर निगरानी और वायु श्रेष्ठता को नई चुनौती मिल रही है। पाकिस्तान-चीन की सैन्य साझेदारी पहले से ही मजबूत थी, जिसमें अब तुर्की का तकनीकी और वैचारिक समर्थन एक नया कारक बन चुका है।

इसके अतिरिक्त, चीन की 'String of Pearls' नीति, जो हिंद महासागर में रणनीतिक बंदरगाहों का एक नेटवर्क तैयार कर रही है (ग्वादर, हंबनटोटा, चिट्टागोंग, क्याउकप्यू आदि), भारत के चारों ओर घेराव की स्थिति उत्पन्न करती है। इसमें अब तुर्की और पाकिस्तान का सक्रिय सहयोग भारत की सुरक्षा रणनीति को और अधिक जटिल बना देता है।

4. भारत की भू-रणनीतिक चुनौतियाँ

1. दो मोर्चों पर युद्ध की आशंका (चीन-पाकिस्तान)

भारत एक दुर्लभ भू-राजनीतिक स्थिति में है जहाँ उसे अपने दो पड़ोसी देशों – चीन और पाकिस्तान – से एक साथ सैन्य टकराव की आशंका बनी रहती है। डोकलाम (2017), गलवान घाटी (2020), और तवांग (2022) जैसी घटनाओं ने चीन के साथ सीमा पर तनाव को बार-बार जन्म दिया है। वहीं पाकिस्तान के साथ जम्मू-कश्मीर और पंजाब सीमाओं पर निरंतर संघर्ष विराम उल्लंघन और घुसपैठ के प्रयास होते रहे हैं। दो मोर्चों पर संभावित युद्ध की स्थिति में भारत की सैन्य रणनीति, संसाधन वितरण और लॉजिस्टिक संरचना पर भारी दबाव पड़ सकता है।

2. कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त वैश्विक दबाव की रणनीति:

कश्मीर एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे चीन, पाकिस्तान और अब तुर्की मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार-बार उठाते हैं। संयुक्त राष्ट्र, OIC (Organization of Islamic Cooperation) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। इसके साथ ही चीन ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर को "विवादित क्षेत्र" बताने की रणनीति अपनाई है। इस त्रिपक्षीय गठजोड़ का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक रूप से घेरना और आंतरिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बनाना है।

3. समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन-तुर्की की भूमिका:

हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) भारत की ऊर्जा और व्यापार आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन का "String of Pearls" रणनीति – जिसमें श्रीलंका (हंबनटोटा), पाकिस्तान (ग्वादर), म्यांमार (क्यौकफ्यु) और जिबूती जैसे स्थानों पर बंदरगाह विकास शामिल है – भारत की समुद्री घेराबंदी का संकेत देता है। अब तुर्की भी अरब सागर और अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में नौसैनिक प्रशिक्षण एवं रक्षा उपकरणों के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इससे भारत की समुद्री प्रभुता को नई चुनौतियाँ मिल रही हैं।

4. 22 अप्रैल 2025: पहलगाम आतंकी हमला और त्रिपक्षीय सहयोग का संकेत

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर झकझोर दिया। इस हमले में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों ने सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 5 सैनिक शहीद हुए। जांच एजेंसियों की प्राथमिक रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के अनुसार हमलावरों को पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों से प्रशिक्षित किया गया था।

विशेष रूप से चिंता का विषय यह है कि हमले में उपयोग किए गए हथियारों और ड्रोन तकनीक में चीनी निर्मित टैक्टिकल गाइडेंस सिस्टम और तुर्की निर्मित ड्रोन-सहायक गोला-बारूद पाए गए हैं। यह इस बात का ठोस प्रमाण है कि चीन, पाकिस्तान और तुर्की एक समन्वित रणनीति के तहत भारत विरोधी ताकतों को हथियार और तकनीकी सहायता दे रहे हैं। इससे भारत को अब "प्रॉक्सी वॉर" के आधुनिक संस्करण का सामना करना पड़ रहा है।

5. सैन्य आधुनिकीकरण और डिप्लोमैटिक प्रयासों की आवश्यकता

इन भू-रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को दो प्रमुख रास्तों पर समानांतर रूप से काम करना होगा:

(A) **सैन्य आधुनिकीकरण**:

भारत को अपनी थल, जल और वायु सेना के आधुनिकीकरण की गति बढ़ानी होगी। स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बल देने के साथ ही राफेल जैसे हाई-एंड प्लेटफॉर्म्स की संख्या बढ़ाना, एंटी-ड्रोन सिस्टम का विस्तार, और AI आधारित युद्ध प्रणाली विकसित करना समय की मांग है।

© 2025 Dr. Arvind Kumar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

(B) कूटनीतिक संतुलन:
भारत को अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ सहयोग को गहराना होगा। QUAD, I2U2 और BIMSTEC जैसे मंचों पर सक्रिय भागीदारी और Global South देशों के साथ संबंधों को मजबूती देना, चीन-पाक-तुर्की त्रिकोण के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगा।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत की स्थिति

यूक्रेन युद्ध और गाजा संघर्ष जैसे वैश्विक घटनाक्रमों के बीच भारत को अब और भी सतर्क रणनीति अपनानी होगी। कूटनीति के स्तर पर भारत को अपनी तटस्थता (strategic autonomy) बनाए रखते हुए मानवाधिकार, आतंकवाद विरोधी पहल और वैश्विक शांति प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इससे न केवल भारत की छवि सुदृढ़ होगी, बल्कि चीन-पाक-तुर्की गठजोड़ द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का भी प्रभाव कम होगा।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया

भारत ने हाल के वर्षों में वैश्विक भू-राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति अपनी रणनीतिक प्रतिक्रिया को बहुआयामी बनाया है, जिसमें सैन्य, कूटनीतिक, तकनीकी और आर्थिक स्तरों पर समन्वित प्रयास दिखाई देते हैं। सबसे पहले, भारत की बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी उल्लेखनीय रही है। क्वाड (QUAD) — जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं — के माध्यम से भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी समुद्री व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2021 और 2022 में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलनों में साइबर सुरक्षा, आपदा राहत, वैक्सीन डिप्लोमैसी और समुद्री निगरानी को लेकर संयुक्त परियोजनाएं शुरू की गईं। इसी प्रकार, आई2यू2 (I2U2 – India, Israel, UAE, USA) के अंतर्गत कृषि, जल, ऊर्जा, परिवहन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है; 2022 में आयोजित आई2यू2 शिखर बैठक में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारत में 2 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की गई, जिससे खाद्य सुरक्षा को बल मिला।
दूसरा, भारत ने इज़राइल, फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे प्रमुख देशों के साथ रक्षा सहयोग को विविधीकृत किया है। रूस के साथ पारंपरिक रक्षा साझेदारी के तहत भारत ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली प्राप्त की, जबकि अमेरिका के साथ COMCASA (2018), LEMOA (2016), और BECA (2020) जैसे तीनों मूलभूत समझौतों पर हस्ताक्षर कर रणनीतिक अंतर-संचालन (interoperability) को सुदृढ़ किया। फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों की डील (2016) और स्कॉर्पीन पनडुब्बी निर्माण सहयोग (P-75 प्रोजेक्ट) इसके उदाहरण हैं। वहीं इज़राइल से भारत ने हेरॉन ड्रोन, स्पाइक मिसाइल और उन्नत निगरानी प्रणालियाँ प्राप्त की हैं, जिससे सीमावर्ती निगरानी क्षमता में वृद्धि हुई है।
तीसरा, भारत 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 और 2021 में "Negative Import List" जारी की गई, जिसके अंतर्गत 310 से अधिक रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई गई। इसके साथ ही, डिफेंस कॉरिडोर (उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु) की स्थापना, DRDO की तकनीकों का निजी क्षेत्र के लिए हस्तांतरण, और HAL तथा BEL जैसी सार्वजनिक इकाइयों के उत्पादन में विस्तार से भारत रक्षा निर्यातक के रूप में उभर रहा है। SIPRI की 2023 रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने 2022-23 में 16 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया, जिसमें फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की डील प्रमुख है।
चौथा, भारत ने डिजिटल और साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभिन्न अंग बनाया है। 2020 में भारत ने "National Cyber Security Strategy" का मसौदा तैयार किया, जिसमें महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं (Critical Infrastructures) की सुरक्षा, साइबर अपराध की निगरानी और डेटा सुरक्षा पर बल दिया गया। CERT-In (Computer Emergency Response Team - India) द्वारा जारी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख साइबर घटनाएं दर्ज की गईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साइबर सुरक्षा आज भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। इसके अतिरिक्त, भारत क्वाड साइबर समूह और संयुक्त राष्ट्र के Open-Ended Working Group (OEWG) में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर साइबर नियमों के निर्माण में योगदान दे रहा है।
इस प्रकार, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया आज न केवल पारंपरिक सैन्य और कूटनीतिक चैनलों तक सीमित है, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, उत्पादन, साइबर-सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग को एकीकृत कर एक व्यापक और सतत सुरक्षा ढांचा निर्मित किया जा रहा है। यह नीति भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध हो रही है।

निष्कर्ष और सिफारिशें (CONCLUSION & RECOMMENDATION)

भारत के लिए एक सशक्त, संतुलित और कूटनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता: 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले ने दक्षिण एशिया में भू-राजनीतिक संतुलन को फिर एक बार अस्थिर कर दिया है। इस हमले की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करना और भारत में रह रहे पाकिस्तानी प्रवासियों को 48 घंटों के भीतर देश छोड़ने का निर्देश देना, इस क्षेत्र में तनाव की तीव्रता को दर्शाता है। यह केवल भारत-पाकिस्तान संबंधों का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक गहराते हुए त्रिकोणीय गठबंधन—पाकिस्तान, चीन और तुर्की—के प्रभाव का भी संकेत है, जो दक्षिण एशिया की स्थिरता और भारत की सुरक्षा नीति के लिए एक दीर्घकालिक चुनौती बन चुका है।

वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

पहलगाम हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं थी, बल्कि एक संदेश था—एक संगठित राजनीतिक-सैन्य गठबंधन की ओर से, जो भारत के भीतर अस्थिरता फैलाने को एक रणनीतिक औजार बना रहा है। इस संदर्भ में पाकिस्तान की हालिया आक्रामक नीति—चाहे वह जलस्रोतों को हथियार बनाने की कोशिश हो या विदेश नीति में आक्रामकता—उसके रणनीतिक संरक्षक चीन और वैचारिक साझेदार तुर्की से प्रेरित दिखती है।
चीन, जो पहले से ही पाकिस्तान के साथ CPEC (चाइना-पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर) के माध्यम से आर्थिक-रणनीतिक गठजोड़ बना चुका है, अब समुद्री सुरक्षा (Maritime Security) और डिजिटल निगरानी प्रणाली के क्षेत्र में पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान कर रहा

© 2025 Dr. Arvind Kumar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

है। वहीं तुर्की, पाकिस्तान के धार्मिक और सांस्कृतिक विमर्शों को बल देते हुए भारत-विरोधी नैरेटिव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दे रहा है, खासकर कश्मीर मुद्दे को लेकर।

क्षेत्रीय समन्वय और भारत की भूमिका

भारत के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह इस त्रिकोणीय गठबंधन को केवल एक द्विपक्षीय चुनौती के रूप में न देखकर एक बहुस्तरीय रणनीतिक खतरे के रूप में समझे। दक्षिण एशिया की स्थिरता अब केवल सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं है, बल्कि कूटनीतिक कौशल, क्षेत्रीय समन्वय और बहुपक्षीय साझेदारी पर भी निर्भर करती है।

भारत को QUAD, BIMSTEC और SCO जैसे मंचों पर अपनी सक्रियता को और तेज करना होगा, ताकि चीन की रणनीतिक गहराई को सीमित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के साथ एक विश्वास-आधारित संबंध विकसित करना भारत की दीर्घकालिक नीति का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।

सिफारिशें: दीर्घकालिक रणनीतिक उपाय

सुरक्षा ढांचे का आधुनिकीकरण: भारत को अपने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी तंत्र को आधुनिक बनाते हुए, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तकनीक आधारित निगरानी (AI, drones, cyber-intelligence) को बढ़ावा देना होगा।

जल कूटनीति (Water Diplomacy): सिंधु जल संधि का पुनर्मूल्यांकन जरूरी है। भारत को जल संसाधनों को रणनीतिक दृष्टिकोण से देखते हुए एक 'Water Security Doctrine' तैयार करनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान को एकतरफा लाभ लेने से रोका जा सके।

आर्थिक प्रतिरोधक क्षमता: पाकिस्तान-चीन-तुर्की गठजोड़ को आर्थिक रूप से संतुलित करने हेतु भारत को मध्य एशिया, खाड़ी देशों और ASEAN के साथ मुक्त व्यापार और ऊर्जा सहयोग समझौतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

सूचना युद्ध और नैरेटिव निर्माण: तुर्की जैसे देश, डिजिटल नैरेटिव के माध्यम से भारत विरोधी विमर्श को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत को रणनीतिक संचार (strategic communication) और डिजिटल डिप्लोमेसी को सशक्त करना चाहिए, जिससे वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा सके।

संयुक्त सैन्य अभ्यास और रणनीतिक गठबंधन: भारत को फ्रांस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ संयुक्त अभ्यास को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन का एक स्पष्ट संकेत जाए।

प्रवासियों और आंतरिक सुरक्षा पर नीति: पाकिस्तान द्वारा प्रवासियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में भारत को भी वीजा नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए और अपने देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों की प्रोफाइलिंग को सख्त बनाना चाहिए।

राजनयिक प्रतिक्रिया: संयुक्त राष्ट्र, ओआईसी और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में पाकिस्तान, चीन और तुर्की की आक्रामकता को उजागर करते हुए भारत को कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए।

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया एक संवेदनशील भूराजनैतिक क्षेत्र है, जहां भारत की स्थिरता पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ी है। पाकिस्तान, चीन और तुर्की का उभरता गठजोड़ केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि एक 'New Geostrategic Reality' है, जिसे भारत को गंभीरता से समझना होगा। इसलिए, भारत को चाहिए कि वह एक समग्र, लचीली और सक्रिय रणनीति अपनाए—जिसमें सैन्य शक्ति, आर्थिक सामर्थ्य, कूटनीतिक प्रभाव और तकनीकी दक्षता—सभी समाहित हों। तभी भारत न केवल इस त्रिकोणीय गठबंधन की चुनौती का सामना कर सकेगा, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थिरता का प्रमुख आधारस्तंभ भी बना रहेगा।

सन्दर्भ सूची

Books

1. Burki SJ. *Pakistan's Foreign Policy: A Concise History*. Oxford: Oxford University Press; 2006.
2. Dalacoura K. *Turkey's Foreign Policy in the 21st Century: A Changing Role in World Politics*. London: Routledge; 2008.
3. Hansen V. *The Silk Road: A New History*. Oxford: Oxford University Press; 2012.
4. Zhang Z. *The China-Pakistan Economic Corridor: A New Frontier of Development and Cooperation*. Singapore: Springer; 2017.

Journal Articles

5. Singh KP. China-Pakistan-Turkey relations and India's strategic dilemma. *Asian J Comp Polit*. 2023;9(3):201–20.
6. Khan R. Strategic implications of the China-Pakistan-Turkey nexus for South Asia. *J Contemp Asia*. 2018;48(4):498–515.
7. Malik J. The geopolitics of the Belt and Road Initiative in South Asia. *Strategic Stud Q*. 2020;14(2):132–45.
8. Rao V. South Asian security dynamics: The Turkey-Pakistan-China nexus. *South Asian Stud*. 2022;34(2):88–104.

Newspapers and Magazines

9. The Hindu. China-Pakistan-Turkey relations: A growing geopolitical challenge for India. *The Hindu*. 2024 Mar 12.
10. The Diplomat. Turkey's increasing influence in South Asia. *The Diplomat*. 2023 Feb 8.
11. The Times of India. India and the China-Pakistan-Turkey nexus: A strategic review. *The Times of India*. 2023 Dec 5.
12. The Express Tribune. CPEC: An evolving Sino-Pakistani-Turkish partnership. *The Express Tribune*. 2023 Jan 25.
13. Foreign Policy. South Asia's emerging geopolitics: China, Pakistan, and Turkey. *Foreign Policy*. 2023 Nov 14.

© 2025 Dr. Arvind Kumar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Web Sources

14. Council on Foreign Relations. The China-Pakistan-Turkey nexus: Implications for India [Internet]. 2024 Apr 20 Available from: https://www.cfr.org
15. The Diplomat. Analyzing the China-Pakistan-Turkey relationship and its strategic impact on India [Internet]. 2024 Mar 28 Available from: https://www.diplomat.com
16. GlobalSecurity.org. China-Pakistan-Turkey relations: A regional power play [Internet]. 2024 Feb 10 Available from: https://www.globalsecurity.org
17. Brookings Institution. Strategic implications of China-Pakistan-Turkey cooperation in South Asia [Internet]. 2024 Mar 18 Available from: https://www.brookings.edu
18. Pakistan Today. Pakistan's strategic relations with China and Turkey [Internet]. 2024 Feb 22 Available from: https://www.pakistantoday.com.pk

Reports

19. Institute of Strategic Studies Islamabad. China-Pakistan Economic Corridor: Strategic implications for regional security [Internet]. Available from: https://www.issi.org.pk
20. Middle East Institute. Turkey's rising influence in Asia: Geopolitical shifts and alliances [Internet]. Available from: https://www.mei.edu

Creative Commons (CC) License

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

About the Authors

डॉ. अरविंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जो रक्षा और सामरिक अध्ययन विभाग आचार्य नरेंद्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोंडा,में कार्यरत हैं। आपके राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 35 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं ।आपने "चैंजिंग डाइमेंशन्स ऑफ इंडियाज डिफेंस मैकेनिज्म" नामक पुस्तक लिखी है।

© 2025 Dr. Arvind Kumar. This open-access article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND). https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/